गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 303
दि. 07.03.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महाराष्ट्र बजट पर सियासी संग्राम, सत्तापक्ष ने बताया विकास का मार्ग तो विपक्ष ने कहा 'ठेकेदारों का दस्तावेज'

जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र के वर्ष 2026–27 के राज्य बजट को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बजट पेश होते ही सत्तारूढ़ महायुति सरकार और विपक्षी महा विकास आघाडी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। एक ओर सरकार इस बजट को राज्य के समग्र विकास का रोडमैप बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता की जरूरतों से दूर और ठेकेदारों के हितों को प्राथमिकता देने वाला बजट करार दे रहा है। बजट के बाद विधानसभा और राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलों के साथ जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं।

सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल एक साल का वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की दिशा तय करने वाला व्यापक खाका है। सरकार के अनुसार इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और उद्योग जगत सहित समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। महायुति के नेताओं का दावा है कि यह बजट महाराष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक विकास के नए चरण में ले जाने वाला साबित होगा।

उपमुख्यमंत्री ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दस्तावेज ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार सरकार ने योजनाओं को इस प्रकार तैयार किया है कि विकास का लाभ राज्य के दूर-दराज के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक समान रूप से पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से किसानों के लिए घोषित 'अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना' का उल्लेख करते हुए इसे सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उनका कहना है कि इस योजना से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और यह सरकार की किसान हितैषी नीति को दर्शाता है।

सत्तापक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि बजट के चार प्रमुख स्तंभ—प्रगतिशील विकास, टिकाऊ नीतियां, समावेशी दृष्टिकोण और सुशासन—राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आधार बनेंगे। उनका मानना है कि यह बजट भविष्य में 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भी सरकार के नेताओं ने बजट की सराहना की है। विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'महिला किसान वर्ष' का बजट में उल्लेख होना ऐतिहासिक

है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई नई पहल की हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। उनके अनुसार महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक किलों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर दिया गया जोर भी राज्य की पहचान को मजबूत करेगा।

सत्तापक्ष के अन्य नेताओं ने भी बजट को महाराष्ट्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि इस बजट में राज्य की आर्थिक प्रगति, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के लिए दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी और नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय को सराहनीय बताया। उनके अनुसार इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप यह बजट महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा। नेताओं का कहना है कि राज्य की औद्योगिक क्षमता, बुनियादी ढांचे और निवेश के अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह बजट भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कुछ मंत्रियों ने बजट को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के संतुलन का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि एक ओर ऐतिहासिक किलों और धरोहरों के संरक्षण की योजनाएं बनाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर समृद्धि महामार्ग और बढ़वण बंदरगाह जैसे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को गति देने की योजना भी है। उनके अनुसार यह संतुलन ही महाराष्ट्र की विशिष्ट पहचान को मजबूत करेगा।

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को भी बजट में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। कौशल विकास विभाग से जुड़े नेताओं का कहना है कि 'दक्ष' और 'महिमा' जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने की योजना से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

श्रमिकों के संदर्भ में भी सरकार का दावा है कि नए श्रम कानूनों के लागू होने से औद्योगिक संबंधों में सुधार होगा और श्रमिकों को अधिक सुरक्षा तथा अधिकार मिलेंगे। कामगार विभाग के अनुसार चार नए लेबर कोड लागू होने से उद्योगों और श्रमिकों के बीच संतुलन स्थापित होगा तथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।

हालांकि सत्तापक्ष की इन दलीलों के विपरीत विपक्ष ने इस बजट की कड़ी आलोचना की है। महा विकास आघाडी के नेताओं का आरोप है कि यह बजट आम जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय ठेकेदारों और बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने वाला है।

पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों पर सरकार का स्पष्टीकरण, देश में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

जीएनएस)। नई दिल्ली : देश में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी बातें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। सरकार ने कहा है कि भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रही है। अधिकारियों के अनुसार नागरिकों को घबराने या ईंधन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। सरकारी सूत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी Bharat Petroleum Corporation Limited ने भी इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि कंपनी का संचालन पूरी तरह सामान्य है और देशभर में उसके सभी डिपो तथा पेट्रोल पंप नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं। कंपनी ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता में कहीं भी कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के ईंधन मिलता रहेगा।

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जरूर देखने को मिली है, जिससे लोगों के बीच चिंता का माहौल

बना। वैश्विक बाजार में प्रमुख सूचकांक Brent Crude Oil की कीमत लगभग 87 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो अप्रैल 2024 के बाद का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। तेल की कीमतों में यह वृद्धि मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री आपूर्ति मार्गों को लेकर पैदा हुई अनिश्चितताओं के कारण देखी जा रही है।

विशेष रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक Strait of Hormuz को लेकर भी वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। यह समुद्री मार्ग खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल के बड़े हिस्से की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन परिस्थितियों के बावजूद देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है और घरेलू बाजार में किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की नीति अपनाई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि किसी एक क्षेत्र से आपूर्ति प्रभावित हो जाए तो देश के पास अन्य विकल्प उपलब्ध रहें। इसी रणनीति के तहत भारत ने विभिन्न देशों से कच्चे तेल के आयात को संतुलित किया है और नए आपूर्ति स्रोतों के साथ दीर्घकालिक समझौते भी किए हैं। विशेष रूप से Russia से कच्चे तेल के आयात में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले तेल की मात्रा कुल आयात का केवल लगभग 0.2 प्रतिशत थी। लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार में हुए बदलावों के बाद भारत ने इस स्रोत का अधिक उपयोग करना शुरू किया। फरवरी 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 के दौरान भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 1.04 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया। यह मात्रा भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर कम करने में भी मदद मिल रही है। इस बीच कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया था कि देश की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited बंद हो गई है, जिसके कारण ईंधन की कमी हो सकती है। सरकार ने इन खबरों को भी पूरी तरह गलत बताया है। अधिकारियों के अनुसार एमआरपीएल सहित देश की सभी प्रमुख रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और उनके पास पर्याप्त कच्चे तेल तथा तैयार ईंधन का भंडार मौजूद है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने पिछले एक दशक में अपनी रिफाइनिंग क्षमता को काफी मजबूत बनाया है। देश में कई बड़ी रिफाइनरियां स्थापित हैं जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात के लिए भी पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करती हैं। यही कारण है कि किसी एक रिफाइनरी में तकनीकी समस्या होने पर भी पूरे देश की आपूर्ति प्रभावित नहीं होती।

नारी शक्ति का नया सूर्योदय: गुजरात में तीन महिला IPS को बड़ी जिम्मेदारी, शासन में जागी विश्वास की नई ज्योति

जीएनएस)। अहमदाबाद। भारत की संस्कृति में नारी को सदैव शक्ति, धैर्य और साहस का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल से ही यह विश्वास रहा है कि जब नारी अपने संकल्प और कर्तव्य के साथ आगे बढ़ती है तो समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है। कुछ ऐसा ही प्रेरणादायक दृश्य इन दिनों गुजरात में देखने को मिला है, जहां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक पहले राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन में एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने नारी शक्ति के प्रति विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। यह निर्णय केवल प्रशासनिक फेरबदल भर नहीं है, बल्कि यह उस विचार का प्रतीक है जिसमें महिलाओं को नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है।

गुजरात सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए 37 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बदलाव की सबसे खास बात यह है कि पहली बार राज्य में तीन तेजतर्रार महिला आईपीएस अधिकारियों को एक साथ बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह निर्णय राज्य के गृह विभाग की ओर से लिया गया है, जिसकी कमान उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में Harsh Sanghavi संभाल रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को 'शक्ति प्रयोग' के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पुलिस व्यवस्था

में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव दोनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में जिन तीन महिला आईपीएस अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, उनमें Gagandeep Gambhir, Parikshita Rathod और Vidhi Chaudhary शामिल हैं। इन तीनों अधिकारियों को अलग-अलग महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है, जहां से वे राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेंगी।

यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में पुलिस तंत्र को अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधारों की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में गुजरात के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में K. L. N. Rao कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यभार संभालने के बाद यह पुलिस विभाग का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उन्होंने पद संभालने के बाद राज्य के कई बड़े शहरों का दौरा किया, क्राइम कॉन्फ्रेंस आयोजित की और पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए विभिन्न रेंज का निरीक्षण किया। इन्हीं बैठकों और विचार-विमर्श के बाद पुलिस प्रशासन में इस बड़े फेरबदल की जमीन तैयार हुई। गुजरात सरकार ने पुलिस तंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए एक नई रेंज की स्थापना भी की है। अब तक राज्य में कुल नौ पुलिस रेंज हुआ करती थीं, लेकिन अब बनासकांठा रेंज के गठन के साथ यह संख्या बढ़ गई है। इस नई रेंज की कमान आईपीएस परीक्षिता राठौड़ को सौंपी गई है। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नई रेंज के संचालन और व्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।

जहां तक आईपीएस गगनदीप गंभीर का प्रश्न है, वे मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं और अपनी तेजतर्रार कार्यशैली के कारण लंबे समय से प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय रही हैं। वर्ष 2004 बैच की यह अधिकारी अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इतिहास विषय में एमए करने के बाद डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में एमफिल की पढ़ाई भी की है। अब उन्हें गुजरात पुलिस की स्टेट मॉनिटरिंग सेल यानी एसएमसी की जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्य में अपराध नियंत्रण के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

यह वही सेल है जो पूरे राज्य में शराब तस्करी, संगठित अपराध और अन्य गंभीर मामलों पर नजर रखती है। इस सेल को किसी भी जिले में जाकर कार्रवाई करने का अधिकार होता है और यह सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करती है। इससे पहले यह जिम्मेदारी आईपीएस निर्लिप्त राय के पास थी। अब इस महत्वपूर्ण दायित्व को गगनदीप गंभीर को सौंपा गया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर बड़ा भरोसा जताया है।

सूरत में बिल्डरों की धोखाधड़ी: अधूरे प्रोजेक्ट, बुकिंग राशि फंसी; उपभोक्ता न्याय की मांग कर रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत शहर के विभिन्न इलाकों में शंकर मारवाड़ी जैसे बिल्डर, जो दलालों के माध्यम से उपजाऊ कृषि भूमि खरीदकर केवल एक चौथाई भुगतान करते हैं, किसानों को लाल पानी से रुला रहे हैं। वे ओफिरा मार्केट के नाम पर परियोजना बनाने का सपना दिखाते हैं। बुकिंग के नाम पर ग्राहकों से 35% से 40% अग्रिम राशि लेकर, अधूरी डायरी और सौदे की पर्चियां बनाकर, दलालों के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं, परियोजना को अधूरा छोड़ देते हैं और 400 वीडियो कॉल करके बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। जब ऐसे बिल्डर, जिनकी परियोजनाएं 8 से 10 साल के इंतजार के बाद भी पूरी नहीं हुई हैं, जिनके कारण बुकिंग के नाम पर पैसे देने वाले मध्यम वर्ग के दुकानदारों का सुनहरा भविष्य बन गया है, शंकर मारवाड़ी जैसे बिल्डरों की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, तो सूरत नगर निगम सहित कलेक्टर को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और

जनहित में उनकी परियोजनाओं की नीलामी करके मध्यम वर्ग के दुकानदारों को बुकिंग की रकम वापस करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो शंकर मारवाड़ी पर भूमि हड़पने का आरोप लगाकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

शून्य त्रुटि एजेंसी

क्योंकि जब व्यापारी ऐसे बेईमान बिल्डरों की परियोजनाओं में सुनहरे सपनों के साथ दुकानें बुक करते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक दुकानें कब आवंटित की जाएंगी? या जब वे अपना पैसा वापस लेने बिल्डर के कार्यालय जाते हैं, तो

बिल्डर खुद पैसा लेने आए व्यापारियों को गाली देता है, धमकाता है, धक्का देता है, पीटता है और मां-बहन की तरह उनका अपमान करता है, जिससे व्यापारी चुपचाप बैठे रहते हैं। इससे बिल्डरों की धृष्टता उजागर होती है। फिर सवाल यह उठता है कि अगर कोई सरकारी ठेकेदार निविदा के अनुसार समय सीमा के भीतर अपनी परियोजना पूरी नहीं करता है, तो क्या सरकार द्वारा उसे जुर्माना लगाने के साथ-साथ ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और अन्य परियोजनाओं से बाहर कर दिया जाना चाहिए? इसी तरह, शंकर मारवाड़ी जैसे बिल्डरों की धूल भरी परियोजनाओं के लिए, उनके आर्किटेक्टों के लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ बिल्डर को भी ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और उनकी नई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। और सरकार को कलेक्टर द्वारा लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी परियोजनाओं को कानूनी रूप से अपने कब्जे में लेना चाहिए, सार्वजनिक नीलामी आयोजित करनी चाहिए और परियोजना का ठेका अन्य व्यक्तियों को देना चाहिए, परियोजना को पूरा करना चाहिए और बुक करने वालों को दुकानें आवंटित करनी चाहिए या पैसा वापस करना चाहिए।

दरअसल, उक्त निर्माण कार्यों की जांच करना सूरत नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सूरत नगर निगम द्वारा अनुमोदित योजना, निर्माण के लिए जारी अनुमति पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (एनओसी), निर्माण प्रमाण पत्र (बीयूसी) आदि का बिल्डरों द्वारा पालन किया गया है या नहीं, और क्या बिल्डर ने परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा किया है या नहीं, इसकी जांच करना नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी यह काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि अधिकारी बिल्डरों के साथ मिलीभगत करके घोटालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं शंकर मारवाड़ी जैसे बिल्डर ग्राहकों को ठग रहे हैं, जिससे भोले-भाले मध्यमवर्गीय व्यापारी ऐसे बिल्डरों के धोखे का शिकार हो रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन आपूर्ति मंत्री के आशीर्वाद से, शंकर मारवाड़ी जैसे कई बिल्डर, जो कभी सरकारी सस्ते भोजन की दुकान चलाते थे और अब बिल्डर बन गए हैं, सूरत के विभिन्न क्षेत्रों में अधूरे प्रोजेक्ट छोड़कर बुकिंग के नाम पर अग्रिम राशि लेकर ग्राहकों को ठग रहे हैं। अब, विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ठगे गए ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। यदि सूरत नगर निगम के नगर आयुक्त और कलेक्टर द्वारा बिल्डरों के पीड़ितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र उपभोक्ताओं के हित में न्याय की लड़ाई लड़ने और बिल्डरों सहित सरकारी व्यवस्था को कानून से अवगत कराने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करेगा।

संपादकीय

नीतीश का अप्रत्याशित कदम

ऐसा लगता है कि बिहार में पहले से लिखी स्क्रिप्ट को अमली-जामा पहनाने का उपक्रम शुरू हो गया है। जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिये नामांकन के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम का महत्व कितना अधिक है,यह नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पटना पहुंचने से पता चलता है। बहरहाल, यह तय हो गया है कि बिहार की राजनीति में दो दशकों के बाद राज्य की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार, जिन्होंने चार माह से भी कम समय पहले रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से इस प्रतिष्ठित कुर्सी को छोड़ने को तैयार हैं। अब 75 वर्षीय नीतीश कुमार आगामी राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल, विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए पर्याप्त बहुमत के कारण उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। निष्कर्ष यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में सफल होने के बाद उनका मुख्यमंत्री के रूप में दो दशक पुराना सफर समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य में उनका अगला उत्तराधिकारी भाजपा से ही आएगा। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा ने जो अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके चलते ही नीतीश को फिर से सत्ता में बने रहने में मदद मिली थी। लेकिन तभी राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे कि कालांतर उनको पद छोड़ना ही होगा, अब चाहे यह स्वेच्छा से हो या मजबूरी में। निस्संदेह, उत्तर भारत में बिहार एकमात्र ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां अब तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर अटकलें लगायी जा रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो सक्रिय राजनीति में अभी नये हैं, नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

बहुत संभव है बिहार में भाजपा की महत्वाकांक्षा को देखते हुए जेडीयू अपनी पार्टी का जनाधार बनाये रखने के लिये पार्टी के लिये उपमुख्यमंत्री पद चाह रही हो। हो सकता है कि सत्ता में अचानक आने वाले इस बड़े बदलाव को लेकर कुछ जेडीयू नेताओं में असंतोष देखने में आए। अनुभवी व उम्रदराज नीतीश कुमार के सामने भी चुनौती है कि कैसे अपने दल के विधायकों को एकजुट रखा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उनकी पार्टी का जनाधार प्रभावित न हो। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को राज्य की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यह घटनाक्रम मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के लिये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह सत्ताधारी गठबंधन की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिशें तेज करेगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने दो दशक की पारी में सहयोग के लिये बिहार की जनता का आभार जताया है तथा अपना दायित्व निभाने की बात कही है। साथ ही राज्यसभा में जाने की तार्किकता का भी जिक्र किया है और विकसित बिहार के संकल्प को फिर से दोहराया है। निस्संदेह, वर्ष 2005 से अब तक, बीच के कुछ महीनों को छोड़कर, उनका सत्ता में बने रहना अभूतपूर्व रहा है। किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। यही वजह है कि जेडीयू में कार्यकर्ताओं का एक वर्ग उनके राज्यसभा में जाने को लेकर निराश है। बहरहाल, अब तक विधान परिषद, बिहार विधानसभा और लोकसभा का सदस्य रहने के बाद, वे राज्यसभा के भी सदस्य बन जाएंगे। वहीं राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस बिहार की सत्ता में होने वाले बदलाव को जनता के साथ छल बता रही है। इसे जनादेश के विरुद्ध कदम बताया जा रहा है। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से बिहार की जनता हतप्रभ है। यह सब भाजपा के विधानसभा में संख्याबल के दबाव में होना था, लेकिन यह इतना जल्दी हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। वे इसे जेडीयू के संकुचन की शुरुआत बता रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनी रहे शिक्षक की गरिमा

> शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी राज से जारी निरीक्षण संस्कृति नई आर्थिक-शैक्षिक नीतियों की चर्चाओं के बावजूद कायम है। वहीं नीति नियंता मानते रहे कि निरंतर परीक्षाओं से शिक्षा की गुणवत्ता उच्च होगी व अध्यापक सतर्क रहेंगे। जबकि असल में शिक्षक की खुशी और गरिमा ही कक्षा में कड़ी मेहनत की बेहतर गारंटी है। तकनीकी मदद से परीक्षाओं ने अध्यापन कमजोर किया।

वर्ष 1990 के दशक के मध्य में नई आर्थिक नीतियों से जो बड़ी उम्मीदें जगी थीं, उनमें से एक यह थी कि लाइसेंस-इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। शायद काम-धंधे की दुनिया में ऐसा हुआ भी, लेकिन शिक्षा जगत में, 'लाइसेंस' और 'इंस्पेक्शन', दोनों के, तौर-तरीके और मज़बूत हुए। स्कूल शिक्षा में, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक शब्द आम था और इस पद के कई स्तर थे।

महान हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने 20वीं सदी की शुरुआत में 'सब-डिप्टी इंस्पेक्टर' के तौर पर काम किया। उनका आभार कि उन्होंने ब्रिटिश राज में विद्यालय निरीक्षण का क्या मतलब हुआ करता था, इसकी साफ निशानियां अपनी कहानियों में वर्णित की हैं। ऐसा नहीं कि निरीक्षक वाली भूमिकाएं और इंस्पेक्शन संस्कृति बीते ज़माने की हैं : वे आज़ादी और नई आर्थिक एवं शिक्षा नीति के बाद भी बची हैं। स्कूल निरीक्षण आज भी ऐसा आयोजन है, जिसमें जहां निरीक्षण करने वाला विभाग अपनी ताकत प्रदर्शित करता है वहीं स्कूल स्टाफ विनम्रता दिखाता है। उनके पास नर्मी दिखाने के अलावा कोई चारा भी नहीं।

निरीक्षण संस्कृति औपनिवेशिक काल के दिनों से नहीं बदली। हेडमास्टर को सुनिश्चित करना होता था कि स्कूल भवन साफ़-सुथरा दिखे, गलियारे में गमले सजे हों। बच्चों को होशियार और अध्यापकों को काम में खोए दिखना होता था। अगर कहीं छत में छेद होते, तो उन्हें चिथड़ों से या जो भी हाथ लगे, उससे ढांप दिया जाता था। अगर फ़र्श पर गड्ढे होते, तो हेडमास्टर उन्हें छिपाने के लिए कालीन का इस्तेमाल करते थे।

गांधीवादी शिक्षाशास्त्री मार्जोरी साइक्स, जो असल में एक ब्रिटिश नागरिक थीं, ने इस लेखक को बताया कि भारत में होने वाला विद्यालय निरीक्षण इंग्लैंड में निरीक्षण से एकदम उल्ट होता था। वहां हेडमास्टर छेदों के चारों ओर चॉक से गोले खिंचवा देते थे, ताकि सुनिश्चित हो कि वह इंस्पेक्टर की नज़रों में आ जाए और वह मरम्मत का काम करवाए। न कोई डर था, न असलियत छिपाने की ज़रूरत थी।

माना गया था कि उदारवाद की आमद से न केवल व्यापार बल्कि हर क्षेत्र में नौकरशाही कमज़ोर होने के साथ इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में, निरीक्षक राज उल्टा उच्च शिक्षा तक फैल गया। एक्रेडिटेशन (मानकीकरण) और रैंकिंग नई प्रथा के तौर पर शुरू किए गए, और उनकी वजह से निरीक्षण टीमों द्वारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज निरीक्षण अनिवार्य हो गया। जब 'नैक' (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल) एक इंस्पेक्शन टीम भेजती है, तो कॉलेज व यूनिवर्सिटी के अधिकारी कैंपस सजा देते हैं, आगंतुक टीम को प्रभावित करने के लिए शानदार डेटा डिस्प्ले एवं खूबसूरत फ्लेक्स तैयार किए जाते हैं। इसके सदस्य 'अन्य तरीकों से अपनी तसल्ली' करवाए जाने की अपेक्षा रखते हैं -महज़ साफ-सुथरे शौचालयों और पौधे लगाने भर से नहीं। अगर टीम उच्चतम ग्रेड से कम की रैंकिंग देती है, तो बताए गए कारण अकसर असली कहानी नहीं होते। हर कोई जानता है कि संस्थान मुखिया आंगतुकों को खुश करने में नाकाम रहा।

द ट्रिब्यून (19 फरवरी) की एक खबर दिखाती है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान और उसके बाद अध्यापकों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने लुधियाना ज़िले के माछीवाड़ा में एक प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद संबंधित अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूछा गया कि निरीक्षण के दौरान उनकी कक्षा के विद्यार्थी पंजाबी में लिखा क्यों नहीं पढ़ पाए और दिए गए गणित के आसान सवाल क्यों नहीं हल कर पाए? हम बीच-बीच में से चुने गए बच्चों के बारे में नहीं जानते। क्या वे पंजाबी भाषी परिवारों से थे, और वे कब से पंजाबी पढ़ना सीख रहे थे? किस किस्म की पठन सामग्री उपयोग की गई? अध्यापकों को किस किस्म के संस्थानों में प्रशिक्षण मिला? क्या बच्चे उस वक्त घबरा गए, जब अनजान लोगों ने उन्हें अचानक खड़े होकर ज़ोर से पढ़ने और गणित के सवाल हल करने के लिए कहा होगा?

ऐसे सवाल मंत्री की निरीक्षण टीम की नज़र से ओझल हैं। मुझे ज़रा संदेह नहीं कि इसके सदस्यों को पंजाब के डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की दुर्दशा के बारे में पता नहीं होगा। यह ज़रूरी ढांचा था जो अध्यापन स्तर को बनाए रखता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अन्य और कई ढांचे बनाए गए। वे भी अब खस्ताहाल हैं। वास्तव में, अध्यापक नीत शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, निजी शिक्षा संस्थानों में तो हाजिरी भी ज़रूरी नहीं। निरीक्षण टीमों को ऐसी बारीकियों में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें तो बस प्रदर्शन चाहिए- बच्चों का प्रदर्शन जो अध्यापकों की काबिलियत का सबूत दर्शाता हो। माछीवाड़ा की कहानी में एक विडंबना यह है कि वह प्राथमिक विद्यालय 'स्मार्ट' स्कूलों की सूची में शामिल है। इस शीर्षक का मतलब है कि स्कूल इंटर-एक्टिव पेडागॉजी (दोतरफा संवाद से पढ़ाई) के लिए ज़रूरी डिजिटल उपकरणों से लैस है। पिछले एक दशक में डिजिटल उपकरणों पर आधिकारिक विश्वास तेज़ी से बढ़ा है। जिसे कोविड-19 महामारी ने और बढ़ाया। जो कोई बात यह साबित करे कि यह भरोसा सही नहीं, उसका विरोध किया जाता है- और ऐसा इसलिए नहीं कि स्मार्ट स्कूल परियोजना में काफी निवेश किया गया है।

डिजिटल उपकरण कक्षा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करते हैं, जिससे अहसास होता है कि तरक्की बहुत हो रही है। यह अहसास सरकारी स्कूलों में एक प्रतीकात्मक उद्देश्य पूरा करने के लिए है। इस संदेश के दो मुख्य हिस्से हैं : पहला, कि सरकार शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के वास्ते फिक्रमंद है, और दूसरा, कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर कम हो रहा है। यह संदेश शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को सैद्धांतिक आभा प्रदान करता है। निजी एवं सरकारी विद्यालय, दोनों में, अध्यापन और शिक्षक-विद्यार्थी रिश्ते पर इसके असली असर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

बच्चों की तकनीक की मदद से निरंतर परीक्षाओं ने असल अध्यापन को कमजोर किया। स्कूलों को चलाने वाली नौकरशाही मान कर चली थी कि निरंतर परीक्षा प्रणाली से अध्यापक अधिक चौकस एवं जिम्मेदार बनेंगे। यह गलत विचार था, हालांकि कागज़ों पर सही लग रहा था और नीति नियंताओं ने इसे उच्च गुणवत्ता पाने का शॉर्टकट समझ हाथों-हाथ लिया। वे अब भी यह नहीं देख पा रहे कि अध्यापकों की खुशी और गरिमा ही कक्षा में ईमानदार मेहनत की गारंटी है।

यह विचार कोई नया नहीं। चार दशक पहले, दार्शनिक डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाले नेशनल टीचर कमीशन ने यह सब कुछ कहा था। रिपोर्ट में अध्यापकों को आत्मविश्वास से परिपूर्ण और सार्वभौमिक बनाने के लिए कई नीतियां सुझाई गई थीं। अध्यापक प्रशिक्षण को वास्तविकता और अर्थ देने के लिए इसकी सिफारिशों का उद्देश्य सोचने-समझने वाले टीचरों का एक समूह बनाना था, जो हर बच्चे को बेस्ट राह प्रदान करने को फैसले लेने में सक्षम हो।

आयोग की यह कीमती सलाह अब पूरी तरह से भुला दी गई है, हालांकि 2008 में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिशें की थीं। और कुछ साल पहले, पंजाब सहित कई राज्यों में अध्यापकों की सार्वभौमिकता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए उप-जिला स्तरीय ढांचे के रूप में 'इंस्पेक्शन राज' का एक विकल्प सामने आया था। आज यह सब खस्ताहाल हैं।

प्रेरणा

संयम की कसौटी पर परखी जाती है साधना

मानव जीवन में ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का मार्ग जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही कठिन और अनुशासनपूर्ण भी होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए केवल इच्छा या उत्साह ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों की गहरी आवश्यकता होती है। इतिहास और संत परंपराओं में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, जिनमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। एक ऐसा ही प्रेरक प्रसंग मिस्र के महान संत जुन्नुन से जुड़ा हुआ है, जो हमें यह सिखाता है कि संयम और धैर्य के बिना धर्म की दीक्षा लेना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है।

कहा जाता है कि मिस्र में एक समय संत जुन्नुन का बहुत बड़ा सम्मान था। वे अपनी गहन आध्यात्मिक साधना, ज्ञान और विनम्र स्वभाव के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। अनेक लोग उनके पास धर्म की शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए आते थे। संत जुन्नुन केवल बाहरी आडंबर या शब्दों की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि वे अपने शिष्यों को जीवन के वास्तविक सत्य और आत्मसंयम का महत्व समझाते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता।

एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर उत्साह था और आँखों में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा कि वह धर्म की दीक्षा लेना चाहता है और जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाना चाहता है। संत जुन्नुन ने उस युवक को ध्यान से देखा। वे जानते थे कि किसी को भी तुरंत दीक्षा दे देना उचित नहीं होता। पहले यह जानना आवश्यक होता है कि व्यक्ति के भीतर धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण की क्षमता कितनी है।

संत ने उस युवक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास रखी एक छोटी सी संदूकची उठाई और युवक को देते हुए कहा कि इसे नील नदी के किनारे रहने वाले मेरे एक मित्र के पास पहुँचा दो। युवक ने बिना किसी प्रश्न के संदूकची ले ली और यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में उत्साह था कि शायद इस कार्य के बाद उसे संत से दीक्षा प्राप्त हो जाएगी।

युवक रास्ते में चलते हुए अनेक विचारों में खो गया। कुछ दूरी तक तो वह पूरी निष्ठा से चलता रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसके मन में उत्सुकता जागने लगी। उसके मन में विचार आया कि इस संदूकची में आखिर ऐसा क्या है जिसे संत ने अपने मित्र के पास भेजा है। मन की यही जिज्ञासा धीरे-धीरे उसे बेचैन करने लगी।

मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जब तक उसे नियंत्रित न किया जाए, वह बार-बार हमें विचलित करता रहता है। युवक भी उसी स्थिति से गुजर रहा था। उसने कई बार स्वयं को समझाया कि उसे संदूकची नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि संत ने ऐसा करने को नहीं कहा था। लेकिन मन की जिज्ञासा उस पर हावी होती जा रही थी।

अंततः वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने इधर-उधर देखा और जब उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने धीरे से संदूकची खोल दी। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसमें बंद एक चूहा अचानक बाहर कूद पड़ा और तेजी से भाग गया। युवक कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह घबरा गया, लेकिन अब पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं था।

वह खाली संदूकची लेकर संत के मित्र के पास पहुँचा। जब उस व्यक्ति ने संदूकची खोली और उसे खाली पाया, तो उसने युवक की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा कि यह संदूकची तुम्हारे संयम की परीक्षा लेने के लिए भेजी गई थी। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित रख पाते और संदूकची न खोलते, तो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते। लेकिन तुम अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख सके और संदूकची खोल बैठे।

उस व्यक्ति ने आगे कहा कि धर्म का ज्ञान केवल शब्दों या पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मन को स्थिर करना पड़ता है। जिस व्यक्ति में धैर्य और संयम नहीं होता, वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे भीतर अभी भी मन की चंचलता और दुर्बलता मौजूद है। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले तुम अपने मन को मजबूत बनाओ और संयम का अभ्यास करो।

युवक यह सुनकर अत्यंत लज्जित हुआ। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि संत ने यह कार्य किसी साधारण कारण से नहीं दिया था, बल्कि यह उसकी परीक्षा थी। वह विनम्रता के साथ सिर झुकाकर खड़ा रहा।

इस घटना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने निश्चय किया कि वह पहले अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखेगा। उसने संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। धीरे-धीरे उसने समझ लिया कि धर्म का वास्तविक मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है।

यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल उत्सुकता या भावनात्मक आवेग से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मन को अनुशासित करना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के भीतर संयम नहीं होता, वह जीवन के बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकता। संयम ही वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।

आज के आधुनिक जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज मनुष्य के पास अनेक साधन, अवसर और आकर्षण हैं, लेकिन संयम और धैर्य की कमी के कारण वह अक्सर गलत निर्णय ले बैठता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन की अनेक समस्याएँ स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। संत जुन्नुन का यह प्रसंग हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान पाने से पहले स्वयं को योग्य बनाना आवश्यक है। जब मन संयमित हो जाता है, तब ही व्यक्ति धर्म और आध्यात्मिकता के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि मन पर विजय ही सच्ची साधना की शुरुआत है।

तीसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगाँठ से पहले मोदी सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल पद पर फेरबदल कर दिये बड़े सियासी संकेत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल तथा उपराज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस फैसले को व्यापक प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस बदलाव के तहत पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और लद्दाख सहित कई स्थानों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे प्रमुख बदलाव तमिल नाडु के राज्यपाल आरएन रवि के स्थानांतरण के रूप में सामने आया है। उन्हें अब पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह सीवी आनंद बोस का स्थान लेंगे, जिन्होंने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस पिछले साढ़े तीन वर्ष से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा।

तमिल नाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को वहां का नया राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वह केरल में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। चुनावी माहौल को देखते हुए इस नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली और लद्दाख में भी अहम बदलाव हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। संधू लंबे समय तक कूटनीतिक सेवा में रहे हैं और विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी राज्यपाल बदले गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल रहे जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में भी नई नियुक्ति की गई है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। सेना में लंबे अनुभव वाले हसनैन सुरक्षा और रणनीति के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की जगह ली है।

इस फेरबदल में हिमाचल प्रदेश के लिए भी नई नियुक्ति की गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल रहे कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल हालांकि काफी चर्चा में रहा। हम आपको याद दिला दें कि कविंदर गुप्ता को जुलाई 2025 में लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह शहर में हिंसक घटना हुई थी। उस दिन क्षेत्र को संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हालात बिगड़ने पर पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें करगिल युद्ध का एक पूर्व सैनिक भी शामिल था। इस घटना ने देश भर में व्यापक चर्चा को जन्म दिया था।

तमिल नाडु में आर एन रवि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार के बीच संबंध भी काफी तनावपूर्ण रहे। सत्तारुढ़ डीएमके ने कई बार आरोप लगाया कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के समानांतर राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल रवि ने कई विधेयकों को मंजूरी देने में देर की थी। इसके बाद अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और दस विधेयकों को प्रभावी रूप से स्वीकृत मान लिया गया।

राज्यपाल रवि कई बार विधानसभा में सरकार के तैयार भाषण को पढ़े बिना ही बाहर चले गए या फिर अपने विचारों के अनुसार भाषण में बदलाव किया। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि निर्णय उन पर होता तो वे नीट से छूट देने वाले विधेयक को कभी मंजूरी नहीं देते। इन घटनाओं के कारण राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रही।

आरएन रवि का प्रशासनिक और सुरक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं और खुफिया ब्यूरो में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2014 से 2021 के बीच वे नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार भी रहे थे। उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर आरएन रवि की नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की खबर से वे चकित और चिंतित हैं।

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से इस बारे में पहले कोई परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह स्थापित परंपरा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक हितों के कारण यह कदम उठाया गया हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह संविधान की भावना और देश की संघीय संरचना के लिए चिंताजनक स्थिति होगी।

बहरहाल, मोदी सरकार जल्द ही अपने तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों और बदलावों का दौर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि आने वाले समय में मोदी मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होते हैं या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।

अभियान

धर्म, प्रेम और लीला की यात्रा: मथुरा से प्रभास तक श्रीकृष्ण का दिव्य पथ

भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण होते ही भक्त के मन में एक अद्भुत और मोहक छवि साकार हो उठती है। नील वर्ण का दिव्य शरीर, अधरों पर मधुर मुस्कान, बड़ी-बड़ी करुणामयी आंखें, माथे पर सुसज्जित मोरपंख और हाथों में बांसुरी—यह रूप केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि अनंत प्रेम, करुणा, ज्ञान और लीला का प्रतीक है। श्रीकृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्त के जीवन के साथी, मार्गदर्शक और रक्षक हैं। उनके जीवन की कथा केवल पुराणों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम, धर्म और जीवन के गहरे सत्य को समझाने वाली दिव्य यात्रा है। महाभारत और पुराणों के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 125 वर्षों तक पृथ्वी पर अपनी लीलाओं से संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। इस दीर्घ जीवन में उन्होंने अनेक स्थानों पर अपनी दिव्य उपस्थिति से भूमि को पवित्र किया। भारत की यह भूमि आज भी उन पवित्र धामों को अपने हृदय में संजोए हुए है, जहां-जहां श्रीकृष्ण की लीला घटित हुई।

श्रीकृष्ण की लीला यात्रा की शुरुआत मथुरा से होती है। मथुरा केवल एक नगर नहीं, बल्कि वह पवित्र धाम है जहां स्वयं भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया। उस समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी क्रूरता से पूरा नगर भयभीत था और प्रजा दुखी जीवन जी रही थी। ऐसे कठिन समय में देवकी और वसुदेव के घर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वह जन्म किसी सामान्य बालक का जन्म नहीं था, बल्कि यह अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना की घोषणा थी। कारागार की अंधेरी रात में जब भगवान का अवतार हुआ, तब प्रकृति भी जैसे आनंद से झूम उठी थी। भक्तों के लिए मथुरा वह स्थान है जहां भगवान ने यह संदेश दिया कि जब भी संसार में अत्याचार और अधर्म बढ़ेगा, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे।

मथुरा से भगवान श्रीकृष्ण की लीला गोकुल की ओर बढ़ती है। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया, जहां नंद बाबा और माता यशोदा ने उनका पालन-पोषण किया। गोकुल की धरती पर कृष्ण का बचपन बीता और उनकी नटखट बाल लीलाओं ने पूरे गांव को आनंद से भर दिया। कभी माखन चुराना, कभी ग्वाल-बालों के साथ खेलना, कभी यशोदा मैया से मासूम शरारतें करना—इन लीलाओं ने गोकुल को भक्ति और प्रेम से सराबोर कर दिया। भक्त जब गोकुल का स्मरण करते हैं, तो उन्हें भगवान का वह बाल रूप याद आता है जो अपने भक्तों के साथ हंसता, खेलता और प्रेम बांटता है।

इसके बाद श्रीकृष्ण की लीला वृंदावन में और भी अधिक दिव्य रूप में प्रकट होती है। वृंदावन वह भूमि है जहां प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यमुना के तट पर बसी यह पावन भूमि राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की साक्षी है। यहां श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरे ब्रज को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वे बांसुरी बजाते, तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी, वृक्ष और पूरी प्रकृति भी उनके संगीत में डूब जाती। वृंदावन की रासलीला केवल एक नृत्य नहीं थी, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। राधा और गोपियों का प्रेम संसार को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें भक्त स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है।

समय के साथ जब श्रीकृष्ण युवावस्था में पहुंचे, तब उन्होंने वृंदावन को छोड़कर मथुरा लौटने का निर्णय लिया। यह वापसी केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि अधर्म के अंत का समय था। मथुरा पहुंचकर श्रीकृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया और वहां की प्रजा को भय और अत्याचार से मुक्त कराया। मथुरा के लोग आज भी कृष्ण को उस मुक्तिदाता के रूप में याद करते हैं जिसने अन्याय और आतंक का अंत किया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है, तो भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। इसके बाद श्रीकृष्ण की लीला यात्रा समुद्र के किनारे बसे द्वारका नगर तक पहुंचती है। द्वारका वह स्थान है जहां श्रीकृष्ण ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया। यहां उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। द्वारका में उनका जीवन केवल वैभव और सत्ता का नहीं था, बल्कि न्याय, करुणा और धर्म का उदाहरण था। उन्होंने अपनी प्रजा को परिवार की तरह माना और बिना किसी अहंकार के उनका पालन किया। द्वारका के लोग आज भी श्रीकृष्ण को ऐसे राजा के रूप में याद करते हैं जो शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम थे। भगवान श्रीकृष्ण की लीला में कुरुक्षेत्र का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां महाभारत का महान युद्ध हुआ। यद्यपि श्रीकृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनका मार्गदर्शन ही पांडवों की विजय का आधार बना। इसी युद्धभूमि में अर्जुन के मन में जब मोह और भ्रम उत्पन्न हुआ, तब श्रीकृष्ण ने उसे भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान दिया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संतुलन है। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां भगवान ने मानवता को यह सिखाया कि जीवन का सच्चा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है।

हस्तिनापुर भी श्रीकृष्ण की लीला यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। यहां उन्होंने एक शांति दूत और मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध रोकने के लिए अनेक प्रयास किए। उनका उद्देश्य हमेशा शांति और न्याय की स्थापना करना था। हस्तिनापुर में श्रीकृष्ण को एक ऐसे दिव्य साक्षी के रूप में याद किया जाता है जिसने मानवता को यह सिखाया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण करुणा और विवेक है।

जब समय बीतते-बीतते श्रीकृष्ण की लीला अपने अंतिम चरण की ओर पहुंची, तब उनकी यात्रा प्रभास पाटन तक पहुंची। प्रभास पाटन वह स्थान है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला का समापन किया। यहां उन्होंने संसार के शोर और सत्ता से दूर एकांत में अपने अंतिम क्षण बिताए। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम सत्य वैराग्य है। चाहे व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, अंततः उसे इस संसार से विदा लेकर परम सत्य की ओर लौटना ही होता है।

लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की उपस्थिति यहीं समाप्त नहीं होती। जगन्नाथ पुरी वह पवित्र धाम है जहां भक्त मानते हैं कि श्रीकृष्ण का हृदय आज भी विद्यमान है। यहां भगवान जगन्नाथ के रूप में उनकी पूजा होती है। पुरी का यह धाम हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान समय और मृत्यु से परे हैं। वे अपने भक्तों के प्रेम में सदैव जीवित रहते हैं। इन सभी पवित्र धामों की यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं है, बल्कि यह भक्ति की एक गहरी साधना है। मथुरा से लेकर गोकुल, वृंदावन, द्वारका, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, प्रभास पाटन और जगन्नाथ पुरी तक फैली यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्रीकृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे आज भी हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। जब भक्त कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उनके मन में प्रेम, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही श्रीकृष्ण की लीला का चमत्कार है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम सुनते ही हृदय में भक्ति की धारा बहने लगती है। क्योंकि श्रीकृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्त के जीवन का आधार, उसका विश्वास और उसकी आशा हैं। यही कारण है कि संसार बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, लेकिन श्रीकृष्ण की भक्ति और उनकी लीला सदा अमर रहती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अहमदाबाद में बनेगा 'लोटस पार्क', 129 करोड़ की लागत से तैयार होगा अनोखा फ्लोरल डेस्टिनेशन

(जीएनएस)। अहमदाबाद। देश के सबसे ऊँचे स्टैच्यू, आधुनिक स्टेडियम और विशाल शॉपिंग मॉल के बाद अब गुजरात एक और अनोखी पहचान बनाने की तैयारी में है। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी के बीच अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में एक भव्य 'लोटस पार्क' बनाने की योजना की घोषणा की है। लगभग 129 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पार्क अपने डिजाइन, थीम और विविध फूलों की प्रदर्शनी के कारण देश का एक अनोखा पर्यटन स्थल बनने की दिशा में देखा जा रहा है। इस पार्क की पहली झलक जारी होने के बाद से ही शहर के नागरिकों और पर्यटकों के बीच उत्साह देखा जा रहा है।

अहमदाबाद नगर निगम के अनुसार इस पार्क का निर्माण शहर के दक्षिण-पश्चिम जोन के सरखेज वार्ड के शेला इलाके में स्थित घतला झील के पास किया जाएगा। यह स्थान तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में आता है और आने वाले समय में यहां बड़े स्तर पर पर्यटन और मनोरंजन गतिविधियों के केंद्र बनने की संभावना है। नगर निगम का कहना है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 128.82 करोड़ रुपये तय की गई है और इसे आधुनिक तकनीक तथा विशेष डिजाइन के साथ विकसित किया जाएगा।

इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा वास्तुशिल्प होगा। पूरे पार्क को कमल के फूल की आकृति में डिजाइन किया जाएगा, जिससे यह दूर से देखने पर भी एक विशाल कमल के रूप में दिखाई देगा। कमल भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पार्क का स्वरूप भी उसी भावना को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 12,445 वर्ग मीटर होगा और इसे कई अलग-अलग हिस्सों में विकसित किया जाएगा।

नगर निगम की योजना के अनुसार इस पार्क में देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले विशेष फूलों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। पार्क के भीतर अलग-अलग सेक्शन बनाए जाएंगे, जहां हर सेक्शन किसी विशेष राज्य की पहचान से जुड़े फूलों को दर्शाएगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में पाए जाने वाले फूलों को उनके प्राकृतिक स्वरूप और सजावट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पार्क में आने वाले लोगों को भारत की जैव विविधता और फूलों की विविधता के बारे में एक ही जगह पर जानकारी मिल सकेगी।

इस पार्क में एक फ्लोरल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाएगा। इस संग्रहालय में दुनिया के विभिन्न देशों में पाए जाने वाले फूलों की जानकारी, उनकी प्रजातियों और उनके सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह म्यूजियम न केवल पर्यटकों के लिए रोचक होगा, बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। यहां आधुनिक डिजिटल तकनीक और इंटरैक्टिव डिस्प्ले का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोग फूलों की दुनिया के बारे में रोचक तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

अहमदाबाद नगर निगम का मानना है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक पार्क बनाना नहीं है, बल्कि शहर की विरासत और आसपास के इलाकों की सुंदरता को बढ़ाना भी है। इस पार्क के माध्यम से शहर के लोगों को एक ऐसा सार्वजनिक स्थान मिलेगा जहां वे प्रकृति के बीच समय बिता सकेंगे, परिवार के साथ घूमने आ सकेंगे और विभिन्न सांस्कृतिक तथा मनोरंजन गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही यहां फूलों की प्रदर्शनी, थीम आधारित आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना है।

शहर के विकास के संदर्भ में यह परियोजना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अहमदाबाद को पहले ही भारत के प्रमुख शहरी और सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाता है। शहर को विश्व विरासत शहर का दर्जा मिल चुका है और अब उसे नए आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में लोटस पार्क को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है जो शहर की सुंदरता और पहचान को और अधिक मजबूत करेगा।

दरअसल, नगर निगम ने शुरुआत में इस पार्क को गोटा वार्ड में एसजी हाईवे के पास बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में योजना में बदलाव करते हुए इसे शेला क्षेत्र में विकसित करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शेला क्षेत्र में इस पार्क के निर्माण से आसपास के इलाकों का विकास भी तेजी से होगा और यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अहमदाबाद में पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं, जिनसे शहर की पहचान और भी मजबूत हुई है। इनमें साबरमती नदी पर बना अटल ब्रिज भी शामिल है, जो शहर का एक नया लैंडमार्क बन चुका है। यह पैदल चलने के लिए बनाया गया एक आकर्षक पुल है और यहां आने वाले लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था भी की गई है। इस पुल के माध्यम से नगर निगम को आय भी हो रही है और यह स्थान पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय बन चुका है।

इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और तब से यह शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाने लगा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब अहमदाबाद के दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्होंने भी इस अटल ब्रिज का निरीक्षण किया और कुछ समय वहां चहलकदमी करते हुए बिताया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर में विकसित हो रहे ऐसे प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

अहमदाबाद में पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और यहां कई आधुनिक शॉपिंग मॉल तथा व्यावसायिक केंद्र भी विकसित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है, जिसने राज्य को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया है। अब लोटस पार्क जैसी परियोजनाओं से शहर की पहचान को और अधिक समृद्ध बनाने में योगदान दे सकती हैं।

नगर निगम का मानना है कि जब यह पार्क पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब यह न केवल शहर के निवासियों के लिए एक प्रमुख मनोरंजन स्थल बनेगा, बल्कि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। यहां आने वाले लोग प्रकृति की सुंदरता, फूलों की विविधता और आधुनिक डिजाइन का अद्भुत संगम देख सकेंगे।

नारी सम्मान का आर्थिक संकल्प: कामकाजी महिलाओं के लिए नई उम्मीद बना 'यस इसेंस महिला वेतन खाता'

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत की सभ्यता में नारी को केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समृद्धि, करुणा और सृजन की शक्ति माना गया है। जब समाज नारी के श्रम, प्रतिभा और परिश्रम को सम्मान देता है, तब विकास की गति और भी तेज हो जाती है। आज का समय वह है जब महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रहीं, बल्कि शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक और वित्त जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे समय में यदि वित्तीय संस्थान भी महिलाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए विशेष सुविधाएं लेकर आते हैं, तो यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

इसी भावना को ध्यान में रखते हुए देश के निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक Yes Bank ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एक विशेष बैंकिंग पहल की घोषणा की है। बैंक ने कामकाजी महिलाओं की जरूरतों और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'यस इसेंस महिला वेतन खाता' नाम से एक नया वेतन खाता शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पहल केवल एक बैंकिंग सेवा नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए एक विश्वास का संदेश भी है जो अपने परिश्रम और योग्यता के बल पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

समाज में जब कोई महिला अपने श्रम से आय अर्जित करती है तो वह केवल अपने परिवार की आर्थिक मजबूती ही नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे समाज की प्रगति में योगदान देती है। यही कारण है कि आज आर्थिक स्वतंत्रता को महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। बैंकिंग व्यवस्था यदि महिलाओं को सुरक्षित, सरल और लाभकारी वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराती है, तो इससे उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। इसी विचार के साथ तैयार किया गया यह नया वेतन खाता महिलाओं को केवल बैंकिंग सुविधाएं ही नहीं देगा, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवनशैली से जुड़ी सेवाएं और भविष्य की आर्थिक योजना बनाने में भी सहयोग करेगा।

बैंक के अनुसार 'यस इसेंस महिला वेतन खाता' का उद्देश्य पेशेवर और नौकरीपेशा महिलाओं को एक ऐसा समग्र बैंकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से वे अपनी आय, बचत और निवेश की योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें। आज के समय में वित्तीय प्रबंधन केवल पैसे को जमा करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। इसी दृष्टि से इस खाते को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को एक ही मंच पर पूरा कर सके। इस खाते के साथ मिलने वाली सुविधाओं को भी विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बैंक ने घोषणा की है कि इस खाते के साथ ग्राहकों को पहले वर्ष के लिए मुफ्त लॉकर सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा उन महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है जो अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों, आभूषणों या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती हैं। बैंकिंग व्यवस्था में सुरक्षा का यह तत्व हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और लॉकर सुविधा महिलाओं को अतिरिक्त भरोसा प्रदान करती है।

इसके साथ ही बैंक ने स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इस खाते के साथ एक वर्ष के लिए पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा यानी टॉप-अप हेल्थ कवर उपलब्ध कराया जाएगा। आज के समय में स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बन चुका है। अचानक आने वाली बीमारी या चिकित्सा खर्च किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यदि बैंकिंग सेवा के साथ स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा मिलती है, तो यह महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी चार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, बांद्रा टर्मिनस–अहमदाबाद, अहमदाबाद–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तथा अहमदाबाद–पुणे के बीच विशेष किराये पर चार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09029/09030 बांद्रा टर्मिनस – अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09029 बांद्रा टर्मिनस–अहमदाबाद स्पेशल रविवार, 08 मार्च 2026 को 00:05 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर उसी दिन 08:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09030 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल सोमवार, 09 मार्च 2026 को 03:20 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर उसी दिन 11:35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09043/09044 बांद्रा टर्मिनस – अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस–अहमदाबाद स्पेशल सोमवार, 09 मार्च 2026 को 14:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर उसी दिन 22:55 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09044 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल सोमवार, 09 मार्च 2026 को 03:50 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर उसी दिन 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 01154/01153 अहमदाबाद–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एसी स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 01154 अहमदाबाद–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्पेशल सोमवार, 09 मार्च 2026 को 04:00 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर उसी दिन 12:55 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 01153 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–अहमदाबाद स्पेशल शनिवार, 07 मार्च 2026 को 22:05 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से प्रस्थान कर अगले दिन 06:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, सूरत, वसई रोड, ठाणे एवं दादर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (इकोनॉमी) कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 01418/01417 अहमदाबाद – पुणे सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 01418 अहमदाबाद–पुणे स्पेशल सोमवार, 09 मार्च 2026 को 02:00 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर उसी दिन 12:10 बजे पुणे पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 01417 पुणे–अहमदाबाद स्पेशल शनिवार, 07 मार्च 2026 को 17:30 बजे पुणे से प्रस्थान कर अगले दिन 05:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वडोदरा, सूरत, वसई रोड, कल्याण एवं लोनावला स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09029, 09030, 09043, 09044, 01154 एवं 01418 की बुकिंग 07.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अनिल अंबानी समूह पर शिकंजा: रिलायंस पावर से जुड़े ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की आर्थिक और कॉरपोरेट दुनिया में उस समय हलचल मच गई जब वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच करते हुए Enforcement Directorate ने उद्योगपति Anil Ambani से जुड़ी कंपनियों और परिसरों पर व्यापक छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई मुख्य रूप से Reliance Power और उससे संबंधित अन्य संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के संदर्भ में की गई। शुक्रवार सुबह से ही जांच एजेंसी की कई टीमें सक्रिय हो गईं और एक साथ अलग-अलग शहरों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई ने देश के कॉरपोरेट जगत और निवेशकों के बीच भी चर्चा का विषय बना दिया है।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी की लगभग 15 टीमों ने एक समन्वित अभियान के तहत मुंबई और हैदराबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान कंपनी के कार्यालयों, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों तथा समूह से जुड़े अन्य परिसरों सहित लगभग 10 से 12 ठिकानों को जांच के दायरे में लिया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने सुबह के समय ही इन स्थानों पर पहुंचकर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू कर दी। इस तरह की कार्रवाई आमतौर पर तब की जाती है जब किसी मामले में वित्तीय लेन-देन और बैंकिंग गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने की आवश्यकता होती है।

सूत्रों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य सामग्री मिली है। इन दस्तावेजों को कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिन लेन-देन पर संदेह जताया जा रहा है, वे किस प्रकार किए गए और उनमें किन-किन कंपनियों या व्यक्तियों की भूमिका रही। जांच एजेंसी इन दस्तावेजों का विश्लेषण करके यह भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लेन-देन में किसी प्रकार की बैंकिंग अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग के तत्व मौजूद हैं।

जानकारों के अनुसार इस तरह की छापेमारी केवल शुरुआती चरण का हिस्सा होती है। जांच एजेंसी सबसे पहले संदिग्ध कंपनियों और व्यक्तियों के परिसरों से दस्तावेज, कंप्यूटर डेटा, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारी एकत्र करती है। इसके बाद इन सभी दस्तावेजों का तकनीकी और कानूनी विश्लेषण किया जाता है। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता या गैरकानूनी गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं, तो एजेंसी आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करती है।

नवसारी और मरोली स्टेशनों के बीच ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। नवसारी और मरोली स्टेशनों के बीच आरएच गर्डर को डी-लॉन्च करने हेतु 09/10 मार्च, 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 09 मार्च, 2026 को डाउन मेन लाइन पर 10:10 बजे से 13:25 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। इसी प्रकार, 10 मार्च, 2026 को अप एवं डाउन मेन लाइनों पर 12:00 बजे से 15:30 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। इन ब्लॉकों के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:-

10 मार्च, 2026 को रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1.09 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19016 पोरबंदर–दादर एक्सप्रेस को 1 घंटा 10 मिनट रीशेड्यूल किया जाएगा।

2.10 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20968 पोरबंदर–सिकंदराबाद एक्सप्रेस को 1 घंटा 10 मिनट रीशेड्यूल किया जाएगा।

3.10 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22543 बांद्रा टर्मिनस–लालकुआं एक्सप्रेस को 55 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

4.10 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल– भिवानी स्पेशल को 1 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

5.10 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19015 दादर–पोरबंदर एक्सप्रेस को 50 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

6.10 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस को 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

10 मार्च, 2026 को शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

1.10 मार्च, 2026 को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस–उधना स्पेशल, बिलीमोरा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बिलीमोरा से ट्रेन संख्या 09056 उधना–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल के रूप में रिवर्स होगी।

पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल में चार अतिरिक्त कोच जोड़े

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09027/09028 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन संख्या 09027/09028 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल में एक अतिरिक्त एसी 2-टियर कोच तथा तीन अतिरिक्त एसी 3-टियर कोच जोड़े गए हैं। इस प्रकार ट्रेन में कुल 4 अतिरिक्त कोचों की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के फलस्वरूप, 07 मार्च 2026 को मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09027 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल तथा 09 मार्च 2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 09028 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल, अब 15 कोच के स्थान पर 19 कोचों के साथ चलेगी।

यह वृद्धि यात्रियों को बेहतर सुविधा एवं अधिक आराम प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

ट्रेनों के ठहराव, समय तथा कोच संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रविवार, 8 मार्च, 2026 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं,पश्चिम रेलवे का माहिम एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन जम्बो ब्लॉक

(जीएनएस)। रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा शनिवार/रविवार, 7/8 मार्च, 2026 की मध्यरात्रि को 01.00 बजे से 04.30 बजे तक माहिम एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान डाउन स्लो लाइन की सभी ट्रेनें मुंबई सेंट्रल एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलायी जायेंगी। प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण ये ट्रेनें लोअर परेल, माहिम एवं खार रोड स्टेशनों पर डबल हॉल्ट लेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण महालक्ष्मी, प्रभादेवी एवं माटुंगा रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त भी रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। अतः रविवार, 8 मार्च, 2026 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

भावनगर मंडल में पहली बार ई-ऑक्शन के माध्यम से डीआरएम कार्यालय कैंटीन का अनुबंध, डीआरएम श्री दिनेश वर्मा ने किया उद्घाटन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए पहली बार मंडल कार्यालय कैंटीन के संचालन का अनुबंध ई-ऑक्शन (e-Auction) मॉड्यूल के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदान किया गया है। यह अनुबंध M/s Gayatri Enterprise, भावनगर को 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अनुबंध के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया दिनांक 02 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। ई-ऑक्शन के माध्यम से अनुबंध 1,81,100/- प्रति वर्ष के लाइसेंस शुल्क पर अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल अनुबंध राशि 10,68,490/- निर्धारित की गई है।

इसी क्रम में दिनांक 06 मार्च 2026 (शुक्रवार) को मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा द्वारा मंडल कार्यालय कैंटीन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा के साथ मंडल कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे में ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से अनुबंधों में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित होती है। साथ ही इससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार मंडल कार्यालय में नई कैंटीन के प्रारंभ होने से मंडल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती भोजन एवं नाश्ते की सुविधा उपलब्ध होगी।

अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी परिवर्तन की अवधि बढ़ाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालनिक कारणों से ट्रेन संख्या 12933 मुंबई सेंट्रल–वटवा एवं 12934 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में (मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस) किए गए अस्थायी परिवर्तन की अवधि को 07 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है: ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस – वटवा कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 08.03.2026 से 31.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद – बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 08.03.2026 से 31.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे टर्मिनेट (समाप्त) होगी। अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन एवं प्रस्थान का समय यथावत रहेगा।

कर्णावती एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी चेयरकार कोच जोड़ा जाएगा

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–वटवा तथा 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस में 08.03.2026 से 31.03.2026 तक एक अतिरिक्त एसी चेयरकार कोच जोड़ा जाएगा। अब यह ट्रेन 22 एलएचबी कोच के साथ चलेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

31 मार्च तक अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल वंदे भारत 20 कोच रेक के साथ संचालित होगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से 4 अतिरिक्त कोच जोड़े गए है।

यह ट्रेन 09 मार्च से 31 मार्च 2026 तक 16 कोचों के स्थान पर 20 कोच (20 coach Rake) के साथ संचालित होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह पर भावनगर मंडल रेलवे अस्पताल में महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर

(जीएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर दिनांक 06.03.2026 (शुक्रवार) को पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल रेलवे अस्पताल में महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर मंडल रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

यह स्वास्थ्य जांच शिविर विशेष रूप से मंडल की महिला कर्मचारियों एवं उनके परिवार की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया, ताकि वे अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच एवं निगरानी सुनिश्चित कर सकें तथा संभावित बीमारियों की समय रहते पहचान हो सके।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जीवनशैली, तनावपूर्ण कार्य वातावरण एवं अनियमित दिनचर्या के कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा तथा सर्वाइकल कैंसर जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में नियमित एवं वार्षिक स्वास्थ्य जांच इन बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर प्रभावी उपचार एवं रोकथाम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अस्पताल प्रशासन द्वारा किए गए इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और सजग बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

भावनगर मंडल रेलवे अस्पताल प्रशासन ने भविष्य में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ताकि रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

पश्चिम रेलवे
अहमदाबाद मण्डल

ई–निविदा सूचना संख्या : Sr.DEE/ADI/47(2025-26) दिनांक : 03.03.2026

एयर–कंडीशनिंग सिस्टम के संचालन और रखरखाव के अनुबंध के प्रावधान के संबंध में बीजली कार्य

निविदा सं. EL-50-1-ADI-T-57-2025-26

कार्य का नाम: 03 वर्षों की समयावधि के लिए DRM कार्यालय असारवा अंतर्गत एयर–कंडीशनिंग सिस्टम के संचालन और रखरखाव के अनुबंध के प्रावधान तथा अहमदाबाद मण्डल पर रनींग रूम्स के विभिन्न बनावट एवं क्षमता के 334 नंग AC युनिट्स के CAMC के संबंध में बिजली कार्य । **अनुमानित लागत:** ₹ 1,19,14,039.82 **बयाना राशि:** ₹ 2,09,600/– **निविदा जमा करने एवं खुलने की तिथि एवं समय:** दिनांक: 30/03/2026 को 15:00 बजे उसके बाद नहिं एवं दिनांक: 30/03/2026 को 15:30 बजे निविदा खोली जायेगी । **कार्यालय का पता एवं वेबसाईट विवरण:** वरिष्ठ मण्डल बिजली अभियंता, म.रे.प्र. कार्यालय (प.रे.), चामुंडा पुल के पास, जी.सी.एस. अस्पताल के सामने, नरोडा रोड़, अमदुपुरा, अहमदाबाद–382345 **वेब साईट का पता:** www.ireps.gov.in

ADI-299

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक-रतलाम मंडल-पश्चिम रेलवे ने पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को IREPS वेबसाइट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। **केटलॉग सं. लीजिंग-आर टी एम - Leasing-RTM-119,** अनुबंध का प्रकार - **Leasing of SLR compartment, लॉट नं.** Train No.12913- SLR-F1-INDB-NGP, 22191-SLR-F1-INDB-JBP, 12228-SLR-R1-INDB-MMCT, 22944-SLR-F1-INDB-DD, 19307-SLR-R1-INDB-UHL, 14115-SLR-R1-DADN-PRYJ, 22984-SLR-R1-INDB-KOTA, 20416-SLR-R1-INDB-BSB, 20414-SLR-F1-INDB-BSB, 19339-SLR-F1-DHD-BPL, 20916-SLR-F1-INDB-LPI, 20416-SLR-F1-INDB-BSB, 12973-SLR-R1-INDB-JP, 12228-SLR-F1-INDB-MMCT, 19339-SLR-R1-DHD-BPL, 20916-SLR-R1-INDB-LPI, 12973-SLR-F1-INDB-JP, 19817-SLR-F1-RTM-AF, 12465-SLR-R1-INDB-BGKT, 14115-SLR-F1-DADN-PRYJ, 12962-SLR-F1-INDB-MMCT, 12913-SLR-R1-INDB-NGP, 20414-SLR-R1-INDB-BSB, 19817-SLR-R1-RTM-AF, 20917-SLR-F1-INDB-PURI, 22941-SLR-F1-INDB-MCTM, 22941-SLR-R1-INDB-MCTM, 19313-SLR-R1-INDB-PNBE, 12919-SLR-R1-DADN-SVDK, 19817-SLR-F2-RTM-AF, 19307-SLR-F1-INDB-UHL अनुबंध की अवधि-3 वर्ष, ई-नीलामी की तिथि और समय सभी लॉट के लिए ई-नीलामी दिनांक **20.03.2026** को 10:00 बजे प्रारंभ होगी। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। IREPS के ई-ऑक्शन मॉड्यूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

Apex/4/1/495

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

18 मार्च को होगा बड़ौदा डेयरी की मैनेजिंग कमेटी का चुनाव, 1071 प्रतिनिधि करेंगे मतदान

(जीएनएस)। वडोदरा। गुजरात के दुग्ध सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्था Vadodara District Cooperative Milk Producers Union Limited यानी बड़ौदा डेयरी की मैनेजिंग कमेटी के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। वर्ष 2025 से 2030 के कार्यकाल के लिए गठित होने वाली नई मैनेजिंग कमेटी के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी और प्रोविजिनल ऑफिसर, वडोदरा रूरल ने मतदान केंद्रों के निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ ही चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है और डेयरी से जुड़ी सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों में चुनाव को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है।

चुनाव प्रक्रिया गुजरात के सहकारी ढांचे के तहत निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा चुनाव Gujarat Cooperative Societies Act, 1961 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के लिए यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करता है, जिसके तहत चुनाव, प्रशासनिक संरचना और संचालन की व्यवस्था तय की जाती है। इसी कानूनी ढांचे के अनुसार चुनाव अधिकारी ने मतदान केंद्रों का निर्धारण करते हुए विस्तृत आदेश जारी किया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बड़ौदा डेयरी की मैनेजिंग कमेटी के लिए मतदान 18 मार्च 2026 को कराया जाएगा। इस दिन मतदान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया वडोदरा में मकरपुरा रोड स्थित बड़ौदा डेयरी के असेंबली हॉल में संपन्न होगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

इस चुनाव में डेयरी से संबद्ध विभिन्न तालुकों की मिल्क सोसाइटियों के प्रतिनिधि अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कुल 1071 प्रतिनिधियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ये प्रतिनिधि अलग-अलग दुग्ध सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के मतों के आधार पर बड़ौदा डेयरी की नई मैनेजिंग कमेटी का गठन होगा। सहकारी क्षेत्र में यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की दूध उत्पादक समितियों को निर्णय प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व मिल सके।

चुनाव अधिकारी द्वारा जारी आदेश में मतदान व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग जोनों में विभाजित किया गया है। आदेश के अनुसार जोन नंबर 1 से लेकर जोन नंबर 13 तक के अंतर्गत आने वाली दुग्ध

सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के लिए मतदान की व्यवस्था एक ही स्थान पर की गई है। इसके तहत पादरा, कर्जन, वडोदरा, शिनोर, तिलकवाड़ा, डभोई, सावली, डेसर, वाघोडिया, संखेड़ा, बोडेली, नसवाड़ी, पविजेतपुर, छोटाउदेपुर और कांवट जैसे कई तालुकों की मिल्क सोसाइटियों के प्रतिनिधि मतदान करेंगे। इन सभी जोन के लिए मतदान केंद्र के रूप में बड़ौदा डेयरी के असेंबली हॉल को निर्धारित किया गया है। चुनाव अधिकारी ने अपने आदेश में प्रत्येक जोन में शामिल मिल्क सोसाइटियों और उनके अधिकृत मतदाताओं की विस्तृत सूची भी प्रकाशित की है, ताकि सभी प्रतिनिधियों को स्पष्ट जानकारी मिल सके कि वे किस जोन के अंतर्गत आते हैं और उन्हें किस प्रकार मतदान प्रक्रिया में भाग लेना है।

सहकारी संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे, इसके लिए प्रशासन ने आपत्तियों और सुझावों के लिए भी प्रावधान रखा है। यदि किसी मतदाता या संभावित उम्मीदवार को निर्धारित पोलिंग स्टेशनों या चुनाव व्यवस्था को लेकर कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना हो, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 9 मार्च 2026 तय की गई है और उस दिन दोपहर 3 बजे तक संबंधित आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए संबंधित व्यक्ति को चुनाव अधिकारी और प्रोविजिनल ऑफिसर, वडोदरा रूरल के कार्यालय में आवेदन देना होगा। यह कार्यालय रावपुरा स्थित कोठी ऑफिस कंपाउंड में स्थित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

बड़ौदा डेयरी गुजरात के सहकारी दुग्ध आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यह संस्था न केवल दूध संग्रहण और वितरण का कार्य करती है, बल्कि हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका से भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। डेयरी के संचालन और नीतिगत निर्णयों में मैनेजिंग कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस चुनाव को सहकारी क्षेत्र में काफी अहम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डेयरी की नई मैनेजिंग कमेटी आने वाले पांच वर्षों में संस्था के विकास, दूध उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और आधुनिक तकनीक अपनाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाएगी। यही कारण है कि डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियां और उनके प्रतिनिधि इस चुनाव को लेकर विशेष रुचि दिखा रहे हैं।

चुनाव अधिकारी के अनुसार मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान, मतदाता सूची का सत्यापन और मतदान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहे।

कुल मिलाकर बड़ौदा डेयरी की मैनेजिंग कमेटी के लिए होने वाला यह चुनाव सहकारी दुग्ध क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। 18 मार्च को होने वाले मतदान के बाद नई कमेटी का गठन होगा, जो वर्ष 2025 से 2030 तक संस्था के प्रशासन और विकास से जुड़े निर्णयों का नेतृत्व करेगी। सहकारी ढांचे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यह उदाहरण यह भी दर्शाता है कि दुग्ध उत्पादक किसानों की भागीदारी के साथ संस्थाओं का संचालन किस प्रकार किया जाता है।

इंश्योरेंस सेक्टर की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए चैंबर सदस्य, सूरत में आयोजित हुआ विशेष इंडस्ट्रियल विज़िट

(जीएनएस)। सूरत। उद्योग और व्यापार जगत में लगातार बदलते माहौल के बीच विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को समझना आज व्यवसायियों के लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry समय-समय पर अपने सदस्यों के लिए इंडस्ट्रियल विज़िट का आयोजन करता रहता है, ताकि उन्हें विभिन्न उद्योगों और सेवा क्षेत्रों की वास्तविक कार्यप्रणाली से परिचित होने का अवसर मिल सके। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैंबर द्वारा हाल ही में Manshree Insurance Brokers Private Limited का एक विशेष इंडस्ट्रियल विज़िट आयोजित किया गया, जिसमें चैंबर के अनेक सदस्यों ने भाग लेकर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस इंडस्ट्रियल विज़िट का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक समुदाय को इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली तथा व्यवसायिक जोखिमों के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को समझाना था। कार्यक्रम में चैंबर के प्रेसिडेंट Nikhil Madrasi भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने इस पहल को व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उनके साथ चैंबर के कई वरिष्ठ सदस्य, उद्योगपति और उद्यमी भी इस दौरे में शामिल हुए। दौरे के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए इंश्योरेंस ब्रोकिंग उद्योग की मूल अवधारणा और उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग केवल बीमा पॉलिसी बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों की आवश्यकताओं का गहन विश्लेषण

करने और उनके लिए सबसे उपयुक्त बीमा समाधान उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण सेवा है। ब्रोकर्स का मुख्य कार्य ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना होता है, ताकि ग्राहकों को उनके व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप बेहतर कवरेज मिल सके।

इंडस्ट्रियल विज़िट के दौरान चैंबर के सदस्यों को यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ जोखिमों की प्रकृति भी काफी जटिल होती जा रही है। ऐसे में उचित बीमा कवरेज और व्यवस्थित रिस्क मैनेजमेंट किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। कंपनी के विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग प्रकार के बीमा समाधान उपलब्ध होते हैं। कार्यक्रम के दौरान व्यापारिक संस्थानों के लिए आवश्यक इंश्योरेंस कवरेज के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी उद्योग या व्यापारिक संस्था के लिए फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेम्निटी इंश्योरेंस, वर्कमेन कंपेंसेशन इंश्योरेंस और साइबर इंश्योरेंस जैसी कई पॉलिसियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन पॉलिसियों के माध्यम से कंपनियां अपने संभावित वित्तीय नुकसान को काफी हद तक कम कर सकती हैं और संकट की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

इसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। कंपनी के विशेषज्ञों ने बताया कि प्रभावी रिस्क मैनेजमेंट केवल बीमा लेने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें जोखिमों की पहचान, उनका विश्लेषण और उन्हें कम करने के लिए उचित रणनीति बनाना भी शामिल होता है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार व्यवसायिक संस्थाएं संभावित जोखिमों का पूर्व आकलन करके अपनी सुरक्षा को मजबूत बना सकती हैं।

इंडस्ट्रियल विज़िट के दौरान चैंबर के सदस्यों को इंश्योरेंस सेक्टर के व्यावहारिक पहलुओं को करीब से समझने का अवसर मिला। उपस्थित सदस्यों ने कंपनी के विशेषज्ञों से कई सवाल भी पूछे और अपने व्यवसाय से जुड़े जोखिमों के बारे में सलाह प्राप्त की। इस संवाद के माध्यम से उद्यमियों को यह समझने में मदद मिली कि सही बीमा योजना उनके व्यवसाय को किस प्रकार सुरक्षित बना सकती है। इस अवसर पर चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में व्यवसाय का वातावरण अत्यंत प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित हो गया है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, तकनीकी बदलावों और बाजार की अस्थिरता के कारण व्यापारिक संस्थानों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट का महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है।

दरी-पट्टी घोटाले पर गरमाई राजस्थान विधानसभा मंत्री मदन दिलावर की कार्रवाई से सियासी घमासान

(जीएनएस)। जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को उस समय अचानक माहौल गर्म हो गया जब सरकारी स्कूलों में दरी-पट्टी की खरीद को लेकर सामने आए कथित घोटाले पर तीखी बहस छिड़ गई। पंचायती राज विभाग से जुड़े इस मामले ने सदन में हलचल पैदा कर दी और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान राज्य के पंचायती राज मंत्री Madan Dilawar ने डेगाना क्षेत्र के स्कूलों में हुई खरीद-फरोख्त से जुड़ी अनियमितताओं का खुलासा करते हुए सख्त कार्रवाई की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं और इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत उस समय हुई जब विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान डेगाना क्षेत्र के विधायक Ajay Singh Kilak ने सरकारी स्कूलों में दरी-पट्टी

की खरीद से जुड़ा सवाल उठाया। पूरक प्रश्न पूछते हुए उन्होंने यह जानना चाहा कि पिछले वर्षों में इस मद में कितना खर्च किया गया और क्या वास्तव में स्कूलों तक वह सामग्री पहुंची भी या नहीं। इस सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने जो जानकारी दी, उसने सदन में मौजूद सभी सदस्यों को चौंका दिया।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 के बीच डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के लिए दरी-पट्टियों की खरीद के नाम पर लगभग 35 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। उस समय क्षेत्र के विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से यह खरीद प्रस्तावित की गई थी। कागजों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार इस राशि से बड़ी संख्या में दरी-पट्टियां खरीदकर स्कूलों तक पहुंचाई जानी थीं, ताकि बच्चों को बैठने में सुविधा हो सके और स्कूलों की बुनियादी व्यवस्था मजबूत हो सके।

लेकिन जब विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराई गई तो तस्वीर बिल्कुल अलग सामने आई। मंत्री के अनुसार रिकॉर्ड में दरी-पट्टियों की खरीद दर्शाई गई थी, जबकि वास्तविकता में स्कूलों में फर्श या अन्य सामग्री की खरीद दिखाई गई। कई जगहों पर तो यह भी पाया गया कि कागजों में दर्ज सामान वास्तव में स्कूलों तक पहुंचा ही नहीं।

मंत्री मदन दिलावर ने सदन में बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार कुल 288 फर्श स्कूलों तक पहुंचाए जाने की जानकारी दर्ज है, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि उनमें से 171 फर्श का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यानी सरकारी खजाने से पैसा तो निकल गया, लेकिन बड़ी मात्रा में सामान का कोई हिसाब-किताब नहीं मिला। यह स्थिति सीधे-सीधे वित्तीय अनियमितता और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल खरीद प्रक्रिया की गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकारी धन के दुरुपयोग की भी आशंका है। यदि स्कूलों के लिए स्वीकृत सामान बच्चों तक नहीं पहुंचा, तो यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि शिक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर अन्याय भी है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई और प्रारंभिक स्तर पर जिम्मेदारी तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की पाई गई।

राजभवनों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सैयद अता हसनैन और कविंद्र गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारियां

प (जीएनएस)। टना/शिमला। देश की संवैधानिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की नियुक्तियों से जुड़ा अहम निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत सात राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी उपराज्यपाल पदों पर बदलाव किया गया है। पिछले 24 घंटों के भीतर जारी अधिसूचना को केंद्र सरकार की ओर से एक व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है, जिसने कई राज्यों के राजभवनों में नई राजनीतिक और प्रशासनिक ऊर्जा का संचार किया है। राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के राजभवनों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही दिल्ली और लद्दाख में उपराज्यपाल पदों पर भी फेरबदल किया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल और उपराज्यपाल संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्यों तथा केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम योगदान देते हैं।

इसी क्रम में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी Syed Ata Hasnain की नियुक्ति की गई है। सेना में अपने लंबे और गौरवशाली करियर के लिए पहचाने जाने वाले हसनैन ने भारतीय सेना में लगभग चार दशकों तक सेवा दी है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारियां संभालीं और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका उल्लेखनीय मानी जाती है। सेना में रहते हुए उन्होंने रणनीतिक नेतृत्व, सामरिक समझ और जमीनी स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़े विमर्श में सक्रिय रहे। कई मंचों पर वे देश की सुरक्षा नीतियों, कश्मीर के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर अपने विचार रखते रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के लिए एक अहम प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि उनका अनुभव और अनुशासन राज्य की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता Kavinder Gupta को सौंपी गई है। वे इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले कविंद्र गुप्ता का सार्वजनिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण और सक्रिय रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुत कम उम्र में ही सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यों के माध्यम से की थी।

जम्मू शहर के जानीपुर क्षेत्र से संबंध रखने वाले कविंद्र गुप्ता ने स्थानीय स्तर से राजनीति की शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने संगठनात्मक कौशल और जनसंपर्क के बल पर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वे तीन बार जम्मू नगर निगम के महापौर चुने गए, जो उनके जनाधार और लोकप्रियता का प्रमाण माना जाता है। नगर निगम में उनके कार्यकाल के दौरान शहर के बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

राजनीतिक जीवन में उनकी सक्रियता का एक महत्वपूर्ण अध्याय वह भी रहा जब देश में लागू The Emergency in India के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

मुफ्त बिजली का वादा या बढ़ती दरों की तैयारी? हिमाचल में सियासी घमासान तेज

(जीएनएस)। शिमला। हिमाचल प्रदेश में बिजली दरों को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। प्रदेश में सत्तारूढ़ Indian National Congress और विपक्षी Bharatiya Janata Party के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा ने राज्य सरकार पर चुनाव के समय किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार अब बिजली दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि बिजली दरों में वृद्धि की गई तो पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी।

भाजपा की प्रदेश इकाई की ओर से जारी बयान में पार्टी की प्रवक्ता Sandipani Bhardwaj ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार उस वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद सरकार बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। भाजपा का कहना है कि यदि प्रस्तावित वृद्धि लागू होती है तो प्रदेश में बिजली की दरों में लगभग एक रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर बड़ी संख्या में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के लोग पहले से ही महंगाई और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी घोषणाओं के दौरान जिस तरह से जनता को राहत देने की बात कही गई थी, अब वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार को अपने वादों को निभाना चाहिए और बिजली दरों में बढ़ोतरी जैसे कदम उठाने से पहले जनता के हितों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

भारद्वाज के अनुसार यदि प्रस्तावित वृद्धि लागू होती है तो इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इस संभावित बढ़ोतरी से प्रदेश के उपभोक्ताओं पर सालाना लगभग 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। भाजपा का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का बोझ प्रदेश के आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसाय, दुकानदार और औद्योगिक इकाइयां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।

भाजपा ने इस संदर्भ में प्रदेश के विद्युत तंत्र से जुड़े वित्तीय आंकड़ों का भी हवाला दिया है। पार्टी का कहना है कि Himachal Pradesh State Electricity Board ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष लगभग 8593 करोड़ रुपये की राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भाजपा के अनुसार यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बताई जा रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिजली दरों में बदलाव की संभावना बन सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय नियामक आयोग द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष इस संभावित प्रस्ताव को लेकर पहले ही सरकार पर सवाल उठा रहा है।

भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा बिजली प्रबंधन से जुड़ी नीतियों और व्यवस्थाओं में किए गए कुछ बदलावों के कारण प्रदेश के विद्युत बोर्ड को खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ सकती है। उनका कहना है कि जब राज्य की अपनी उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं होती और बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उसका असर स्वाभाविक रूप से बिजली की लागत पर पड़ता है। भाजपा का दावा है कि यदि इस स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो भविष्य में बिजली दरों में वृद्धि की संभावना और बढ़ सकती है।

प्रदेश की राजनीति में बिजली दरों का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में बिजली केवल घरेलू जरूरत ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण आधार है। पर्यटन उद्योग, छोटे व्यवसाय, कृषि से जुड़े कार्य और स्थानीय उद्योग बिजली पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। ऐसे में बिजली दरों में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे-सीधे आम लोगों के जीवन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार बिजली दरों में वृद्धि का फैसला करती है तो पार्टी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इस मामले को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध दर्ज कराया जाएगा। उनका कहना है कि जनता को दिए गए वादों को पूरा करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और यदि सरकार उन वादों से पीछे हटती है तो विपक्ष का कर्तव्य है कि वह जनता की आवाज उठाए।

दर्दनाक सड़क हादसे में बुझ गईं छह जिंदगियां, जशपुर में पलटी यात्री बस से मचा कोहराम

(जीएनएस)। Jashpur / Raipur। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। करडेगा से कुनकुरी की ओर जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में एक मासूम बच्चे सहित छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नौ अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे और वह नियमित रूप से चलने वाली यात्री बस बताई जा रही है। गुरुवार को जब बस करडेगा क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, तभी Goda Amba village के पास अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ ही क्षणों में वहां का दृश्य बेहद भयावह हो गया।

दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने बस की ओर दौड़ लगाई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। कई यात्री बस के अंदर फंसे हुए थे जिन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी सूचना दी। दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य को तेज किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई गई और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए Kunkuri Community Health Center भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। अस्पताल में भर्ती कई यात्रियों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और चिकित्सा दल लगातार उनकी निगरानी कर रहा है।

अधिकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में छह यात्रियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, जिससे हादसे की पीड़ा और भी अधिक गहरी हो गई है। हादसे की खबर जैसे ही आसपास के गांवों में फैली, लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा होने लगी। कई लोग अपने परिचितों और रिश्तेदारों की जानकारी लेने के लिए अस्पताल और दुर्घटनास्थल की ओर पहुंचने लगे।

दुर्घटना की सूचना राज्य के उच्च प्रशासन तक भी पहुंच गई। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की ओर से घायलों के समुचित उपचार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

क्रूड ऑयल वायदा में 583 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 1.61 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.68 लाख रुपये के स्तर पर पहुँचा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 172799.5 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 28159.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 144640.13 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 39386 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5975.86 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16201.57 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 161040 रुपये के भाव पर खूलकर, 161250 रुपये के दिन के उच्च और 159372 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 159673 रुपये के पिछले बंद के सामने 26 रुपये या 0.02 फीसदी की तेजी के संग 159699 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 383 रुपये या 0.29 फीसदी गिरकर 131012 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 42 रुपये या 0.25 फीसदी गिरकर 16457 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 160863 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 161500 रुपये और नीचे में 159404 रुपये पर पहुंचकर, 32 रुपये या 0.02 फीसदी गिरकर 159781 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 161499 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162488 रुपये और नीचे में 160510 रुपये पर पहुंचकर, 161141 रुपये के पिछले बंद के सामने 340 रुपये या 0.21 फीसदी गिरकर 160801 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 267950 रुपये के भाव पर खूलकर, 268991 रुपये के दिन के उच्च और 261398 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 262191 रुपये के पिछले बंद के सामने 205 रुपये या 0.08 फीसदी की तेजी के संग 262396 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 33 रुपये या 0.01 फीसदी की मजबूती के साथ 268852 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 201 रुपये या 0.07 फीसदी गिरकर 268800 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 1862.91 करोड़ रुपये के ट्रेड

दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 5.25 रुपये या 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 1189.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.25 रुपये या 0.39 फीसदी की बढ़त के साथ 322.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 2.5 रुपये या 0.76 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 333.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी चढ़कर 188.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 9480.42 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 7316 रुपये के भाव पर खूलकर, 7940 रुपये के दिन के उच्च और 7308 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 583 रुपये या 7.97 फीसदी की मजबूती के साथ 7899 रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 586 रुपये या 8.01 फीसदी की तेजी के संग 7900 रुपये प्रति बैरल हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 274.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 282.9 रुपये के दिन के उच्च और 271.9 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 273.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 9.1 रुपये या 3.33 फीसदी की तेजी के संग 282.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 9.1 रुपये या 3.33 फीसदी की मजबूती के साथ 282.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 28159.13 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 144640.13 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 16201.57 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39386 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 947.1 रुपये के भाव पर खूलकर, 40 पैसे या 0.04 फीसदी चढ़कर 940 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9810.64 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6390.93 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1137.27 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 380.00 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 4.12 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 341.52 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7437.38 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2031.27 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9749 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 62279 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31362 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 441157 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63368 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7032 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19427 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 71093 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24811 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 29842 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 39380 पॉइंट पर खूलकर, 39386 के उच्च और 39380 के नीचले स्तर को छूकर, 327 पॉइंट घटकर 39386 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 343.9 रुपये की बढ़त के साथ 653.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.65 रुपये की बढ़त के साथ 21.6 रुपये हुआ। सोना मार्च 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 171 रुपये की गिरावट के साथ 677 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 400000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 88 रुपये की गिरावट के साथ 836 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.38 रुपये की गिरावट के साथ 26.67 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो बिना बदलाव के 2.9 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 81.9 रुपये की गिरावट के साथ 256.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.9 रुपये की गिरावट के साथ 13.35 रुपये हुआ।

सोना मार्च 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 62.5 रुपये की बढ़त के साथ 479.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 65 रुपये की बढ़त के साथ 344 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 30 पैसे के सुधार के साथ 14.38 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 297.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.46 रुपये की बढ़त के साथ 2.79 रुपये हुआ।